

सम्पादकीय

जहरीली हवा

सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिवाली के आसपास दिल्ली और इसके सटे इलाकों की हवा में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार काफी हाथ-पांव मारती देखी जाती है, पर उसे सफलता मिलती नजर नहीं आती। अक्सर इस मौसम में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह किसानों के पराली जलाने, पटाखे फोड़ने और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द को बताया जाता रहा है। मगर इस साल इन सभी पहुंचों पर सरकार पहले से सतर्कता बरत रही थी। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द पर अंकुश लगाने के लिए पूरी दिल्ली में जांच दल गठित कर दिए गए थे। किसानों को पराली न जलानी पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से तेयार जेव रसायन का मुफ्त वितरण शुरू किया था, जिससे पराली आसानी से खेतों में ही गल-पच जाती है। पटाखों पर अदालत की तरफ से रोक है। यों भी दिवाली से पहले इतने पटाखे नहीं फोड़े जाते कि उनसे निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को दमघोटू बना दे। मगर इतने एहतियात के बावजूद स्थित यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरे के बिंदु तक पहुंच गया। मंगलवार को दर्ज आंकड़ों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देश के प्रमुख शहरों में सबसे ऊपर था। तीन सौ नौ अंक। आने वाले दिनों में इस स्तर में और बढ़ोत्तरी की संभावना जारी गई है।

जब मोसम सद्द होने लगता है, तो हवा पृथ्वी की सतह के आसपास सिमटने लगती है, फिर उसमें घुले प्रदूषक वातावरण को दमघोट बना देते हैं। पिछले कुछ सालों में तो ऐसा अनुभव रहा कि बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े, लोगों को सुबह टहलने निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई। दमकल की गाड़ियों से पेड़ों पर पानी की बौछार मार कर प्रदूषक तत्त्वों को कम करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में वायु प्रदूषण अवशोषक संयंत्र भी रख लिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जगह वायु प्रदूषण सोखने वाला विशाल संयंत्र भी लगाया है, जिसके नतीजे उत्साहजनक हैं। ऐसे संयंत्र अन्य स्थानों पर भी लगाने की उसकी योजना है। मगर अब यह साफ हो गया है कि तमाम उपायों के बावजूद अगर वायु प्रदूषण पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है, तो इसकी वजहें दूसरी हैं। वायु प्रदूषण का बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसे कम करने के भी कई उपाय सरकार आजमा चुकी है, पर उस पर काबू नहीं पाया जा पा रहा। हालांकि वाहनों पहले से ही ऐसे यंत्र लगाया जाने लगे हैं, जो धुएं को पानी में बदल देते हैं, उसे हवा में घुलने नहीं देते। बसों में सीएनजी इस्तेमाल होने लगी है। अब बैट्री चालित टैक्सियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मगर दुपहिया वाहनों से निकलने वाले धुएं पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दुपहिया वाहनों की वजह से फैलता है। दिवाली नजदीक होने की वजह से आनलाइन खरीदारी पर जोर रहा। ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ज्यादातर दुपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दुपहिया वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए इनसे निकलने वाला धुआं चुनौती बना हुआ है। फिर चोरी-छिपे बहुत सारे धुआं उंगलने वाले छोटे और मंज़ोले उद्योग-धंधे भी दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। इस दिशा में जब तक कोई व्यावहारिक उपाय नहीं निकाला जाएगा, तब तक इस समस्या पर काबू पाना कठिन बना रहेगा।

गांधी-नेहरू को नकारने की कोशिश

पलाश सुरजन

पलाश सुरजन

लोग हाड़-मांस के इंसान थे, रामायण-महाभारत जैसे किसी टीवी धारावाहिक के पात्र नहीं जो पलक झपकते उन सब जगहों पर पहुंच पाते जहां अंग्रेजों का राज था और जिसकी बिना पर यह कहा जाता था कि बरतान साम्राज्य में सूरज कभी नहीं ढूबता। भारत दो सौ सालों तक ब्रिटेन वे अधीन रहा। इस दौरान असंख्य भारतीय अपने-अपने तरीके से अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन उनके संघर्ष को दिशा तो तभी मिली जब महात्मा गांधी भारत आए और आन्दोलन का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथों में लिया।

सिंहा जी एक पूरा आलेख इसी विषय पर लिखते कि आजादी के लड़ाई में गांधी-नेहरू की जरूरत क्यों नहीं थी या उनके बिना भी देश कैसे आजाद हो सकता था, तो बेहतर होता। वे अपनी प्रतिष्ठा के साथ न्याय करते यदि बताते कि उन देशों की परिस्थितियां क्या थीं और तें कितने समय तक गुलाम रहे। क्या ब्रिटेन ने किसी स्व प्रेरणा से उन देशों को मुक्त कर दिया था या वहां भी कोई आन्दोलन चला था और वह आन्दोलन भारत के संघर्ष से प्रेरित था या नहीं। क्या उन देशों में भी वैसंविधान थी जैसी भारत में अभी तक है और क्या उनका आकार-प्रकार भी वैसा था जैसा हमारे देश का है। अगर गांधी-नेहरू वहां नहीं थे तो जिन्ना और सावरकर भी वहां थे या नहीं। और कुछ नहीं तो वे उन देशों की फेहरिस्त ही दे देते जिनकी बात वे अपने ट्वीट में करते हैं। लेकिन सिंहा जी तो आईटी सेल के कारिए की तरह व्यवहार करके खामोश बैठ गए। उन्हें पता है कि ऐसी बेसिर-पैर की बातें पर लोग न केवल आंखें मूँदकर भरोसा कर लेते हैं, उन्हें हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता।

बहरहाल, सिंहा जी और उनके अनुचरों को जान लेना चाहिए वि-

भले ही गांधी-नेहरू उन 53 देशों में नहीं थे, लेकिन उनके अथक संघर्ष ने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला तो गांधी से इस कदर प्रभावित थे कि उन्हें उनके देश में महात्मा गांधी कहा जाता था। गांधी जी की तर्ज पर जूलियस न्येरेरे ने तंजानिया की मुक्ति के लिए अहिंसक आन्दोलन चलाया और अपने देश के राष्ट्रपिता कहलाए। अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले महान नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। स्थांमार में लोकतंत्र की प्रबल समर्थक रहीं आंग सान सू ची गांधी के विचारों से प्रभावित रहीं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ब्राक ओबामा का भी गांधी के विचारों में छढ़ विश्वास है, जिसे वे बार-बार व्यक्त कर चुके हैं। साइप्रस के निकासिया म्युनिसिपल पार्क में गांधी जी की मूर्ति है और वहां के संसद भवन का नाम, नेहरू जी के नाम पर रखा गया है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं, उन पर बात फिर कभी। दरअसल, गांधी जी को भारतीय जनमानस से हटाने की शुरूआत उस दिन से हो गई थी जिस दिन उन्हें स्वच्छ भारत अभियान तक सीमित कर दिया गया था। स्वच्छता के अलावा भी गांधी जी के जो सबक थे, उन सबको किनारे कर दिया गया। नेहरू जी की छवि को तरह-तरह से धूमिल करने की कोशिशें की गईं। इसके बावजूद अनचाहे ही सही, गांधी जी को जब-तब सर नवाना ही पड़ता है और 15 अगस्त के भाषणों में नेहरू जी को याद करना ही पड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई लोकतांत्रिक देश ऐसा होगा जिसका रवैया आजादी दिलाने और देश को सबल-सशक्त बनाने वाले अपने पुरुषों के प्रति ऐसे पाखण्ड और घृणा से भरा होगा। ऐसा न हो कि आने वाले समय में इस कृतघ्नता के दुष्परिणाम हमें भुगतान पड़ें। बकौल अल्लामा इकबाल -

बिजली संकट को टालिए मत, सामना कीजिए

डॉ. भरत झुनझुनवाला

आने वाले समय में ऐसी समस्या पुनः उत्पन्न न हो इसके लिए हमें दो कदम उठाने होंगे। पहली बात यह कि देश में ऊर्जा का खपत कम करना होगा। हमारे पास कोयले के भंडार केवल 150 वर्षों के लिए उपलब्ध हैं और तेल के लिए हम आयातों पर निर्भर हैं इसलिए हमें देश में ऊर्जा के मूल्य को बढ़ाना चाहिए और उस रकम को ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए लगाना चाहिए। जैसे यदि सरकार बिजली का दाम बढ़ा दे और कुशल बिजली की मोटरों को लगाने के लिए सब्सिडी दे तो देश में ऊर्जा की खपत कम होगी लेकिन उद्यमी को नुकसान नहीं होगा और हमारा जीडीपी प्रभावित नहीं होगा। बीते समय बरसात में कोयले की खदानों में पानी भरने से अपने देश में कोयले का उत्पादन कम हुआ था। बिजली का उत्पादन भी कम हुआ और कई शहरों में पॉवर कट लागू किए गए। फिलहाल बरसात के कम होने से यह संकट टल गया है। लेकिन यह केवल तात्कालिक राहत है। हमें इस समस्या के मूल कारणों का निवारण करना होगा अन्यथा इस प्रकार की समस्या बार-बार आती रहेगी। वर्तमान बिजली संकट के तीन कथित कारणों का पहले निवारण करना जरूरी है। पहला कारण बताया जा रहा है कि कोविड संकट के समाप्तप्राय हो जाने के कारण देश में बिजली की मांग बढ़ गई है जिसके कारण यह संकट पैदा हुआ है। यह स्वीकार नहीं है क्योंकि अप्रैल से सितंबर 2019 की तुलना में अप्रैल से सितंबर 2021 में कोयले का 11 फीसदी अधिक उत्पादन हुआ था। इसी अवधि में देश का जीडीपी लगभग उसी स्तर पर रहा। यानी कोयले का उत्पादन बढ़ा और अर्थात् गतिविधि पूर्व के स्तर पर रही। इसलिए बिजली का संकट घटना चाहिए था न कि बढ़ाना चाहिए था जैसा कि हुआ है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि कोयले के खनन में बीते कई वर्षों में निवेश कम हुआ है। बिजली उत्पादकों का रुझान सोलर एवं वायु ऊर्जा की तरह अधिक हो गया है। यह बात सही है सकती है लेकिन इस कारण बिजली का संकट पैदा नहीं होना चाहिए था कोयले के खदान में जितने निवेश की कमी हुई है यदि उतना ही निवेश सोलर और वायु ऊर्जा में किया गया तो कोयले से बनी ऊर्जा में जितनी कमी आई होगी उतनी ही वृद्धि सोलर और वायु ऊर्जा में होनी चाहिए थी। ऊर्जा क्षेत्र में कुल निवेश कम हुआ हो ऐसे सकें नहीं मिलते हैं इसलिए कोयले में निवेश की कमी को संकट का कारण नहीं बताया जा सकता है। हाल में आए बिजली के संकट का मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग दीखता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तरफ बिजली का उत्पादन कम हुआ तंदूसरी तरफ बिजली की मांग बढ़ी है। पहले उत्पादन पर विचार करें। जैसे ऊपर बताया गया है, बीते समय में बाढ़ के कारण कोयले का खनन कम हुआ था। यह बाढ़ स्वयं ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ी है ऐसे सकें मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा कम समय में अधिक मात्रा में होने वे अनुमान हैं जो कि बाढ़ का कारण बनता है। इसलिए बाढ़ को दोष देने के स्थान पर हमको ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान देना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का

ईसाई अल्पसंख्यक और भारतीय प्रजातंत्र

राम पुनियानी

बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमला शुरू होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई परंतु वह तब पहुंची जब हमलावर अपना काम करके जा चुके थे। इसाईयां और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों का उद्देश्य इस आख्यान को मजबूती देना है कि इसाई मिशनरियां हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं।

रप्ट में देश के विभिन्न भागों में इस तरह की घटनाओं के विवरण संकलित किए गए हैं। इस वर्ष ऐसी घटनाएं अनेक स्थानों पर हुईं जिनमें शामिल हैं मऊ (10 अक्टूबर), इंदौर (26 जनवरी), शाहजहांपुर (3 जनवरी), कानपुर (27 जनवरी), बरेली (16 फरवरी), अम्बेडकरनगर (21 फरवरी), प्रयागराज (25 फरवरी), कानपुर (3 मार्च), आगरा (14 मार्च), केरल (22 मार्च), महाराजगंज (19 अप्रैल), बिजनौर (23 जून), गोंडा (25 जून), आजमगढ़ (25 जून), गम्पुर (26 जून) याहुबोली (28 जून) शाहजहांपुर (29 जून) और एया (29

जून), रायबरला (२४ जून), शाहजहापुर (२९ जून), आरया (२९ जून), जौनपुर (३ जुलाई), होशंगाबाद (३ अक्टूबर), महासुमंद (३ अक्टूबर) और भिलाई (३ अक्टूबर)। इस सूची से पता चलता है कि इस तरह की घटनाओं में से अधिकांश उत्तरप्रदेश में हो रही हैं। हरियाणा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ घटनाएं हुई हैं और एक घटना केरल में हुई है। अधिकांश मामलों में हमला ईसाइयों की प्रार्थना सभाओं पर किया गया। आरोप यह था कि ये सभाएं धर्म परिवर्तन का अड्डा हैं। बहुसंख्यक वाद के उभार के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों को

नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अलग-अलग धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों पर अलग-अलग ढंग के आरोप लगाए जाते हैं। इसाईयों के मामले में मुख्य आरोप यह होता है कि वे हिन्दुओं को लालच, कपट और जोर-जबरदस्ती से इंसाई बना रहे हैं। आज से छः साल पहले सन् 2015 में जूलियो रिबेरो, जिन्होंने अत्यंत

जाति है कि

हर्ष वी. पंत

प्रतिबद्धता और इमानदारा से पुलेस आधकारी बतार अपन कतव्या के निर्वहन किया, ने कहा था कि एक ईसाई बतार अचानक मैं अपने आपके इस देश में अजनबी सा महसूस करने लगा हूँ। तब से स्थितियां और खराब ही हुई हैं। भारत में ईसाई विरोधी हिंसा पर नजर रखने वाले एक संगठन प्रोसीक्यूशन रिलाफ के अनुसार सन् 2020 की पहली छैमाही में देश में ईसाईयों को प्रताड़ित करने की 293 घटनाएं हुईं। इनमें से 6 मामलों का अंत हत्या में हुआ। दो महिलाओं का बलात्कार करने के बाद उनके हत्या कर दी गई। दो अन्य महिलाओं और एक दस साल की लड़की की इसलिए बलात्कार किया गया व्यांकि उन्होंने ईसाई धर्म त्यागने से इंकार कर दिया। उत्तरप्रदेश इस मामले में ईसाईयों के लिए सबसे बुरा राज्य था वहां ईसाईयों के खिलाफ नफरत से उद्भूत 63 घटनाएं हुईं। इस संस्था वे संस्थापक शिवू थामस के अनुसार वे केवल वे घटनाएं हैं जिनकी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। यह भी हो सकता है कि अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी जानकारी उन तक न पहुँची हो। चर्चों के लिए काम करने वाले एक अन्य संस्था ओपन डोर्स के अनुसार ईसाईयों को उनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों जीवन में प्रताड़ित किया जाता है। धर्मातरण निरोधक कानूनों (जो अभी नौ राज्यों में लागू हैं) के अंतर्गत उन्हें परेशान किया जाता है। इन कानूनों के अंतर्गत दोषिण्डि तो बहुत कम लोगों की होती है परंतु सालों तक अदालतों के चक्कर लगाना अपने आप में एक सज्ज है। भारत उन दस देशों में शामिल है जहां ईसाईयों का रहना खतरनाक है।

कनाटक सरकार जल्दा ही धमातरण नियंत्रण कानून बनाने वाले हैं। उसने अभी से चर्चों और वहां होने वाले समागमों की जासूसी करवानी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 1 अक्टूबर के आयोजित एक रैली में स्वामी परमात्मानानंद ने भाजपा नेताओं के मौजूदगी में यह आद्वान किया कि धर्मातरण में रत अल्पसंख्यकों का चुन-चुनकर मारा जाना चाहिए। यह आरोप अक्सर लगाया जाता है कि ईसाई मिशनरियों हिन्दुओं को बड़े पैमाने पर ईसाई बना रही हैं।

परतु आकड़े कुछ आर हा कहाना कहत ह। सन् 1971 म इसाई भारत की आबादी का 2.60 प्रतिशत थे। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार उनका प्रतिशत 2.30 था। इसाईयत को विदेशी धर्म बताया जाता है परंतु सन् 52 में सेंट थामस मलाबार टट पर उतरे थे और तब से भारत में इसाई धर्म अस्तित्व में है। कुछ इसाई मिशनरियां खुलकर यह घोषित करती हैं कि उनका उद्देश्य लोगों को इसाई बनाना है परंतु उनमें से अधिकांश दूरस्थ इलाकों में और गरीब दलित समुदायों की बसियों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। इसाई मिशनरियों

द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। इनमें प्रवेश पाने के लिए कड़ी प्रतियोगिता होती है। देश में ईसाई विरोधी प्रचार की शुरूआत सन् 1970 के दशक में हुई जब विहिप और बनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासी इलाकों में घुसपैठ करना शुरू किया। गुजरात के डांग में सन् 1998 में हिंसा हुई। स्वामी असीमानंद, जो कई बम धमाकों के आरोपी है, ने डांग में शबरी कुंभ का आयोजन किया और शबरी माता मंदिर बनवाए। झाबुआ में आसाराम बापू (जो अब जेल में है) के समर्थकों ने इसी तरह के आयोजन किए और इसके बाद झाबुआ में हिंसा हुई। ओडिशा में स्वामी लक्ष्मणानंद ने अपना काम शुरू किया और इसके नतीजे में सन् 2008 में कंधामाल हिंसा हुई। इसके पहले सन् 1999 में बजरंग दल के द्वारा सिंह ने पॉस्टर ग्राहम स्टेन्स की हत्या कर दी थी। उन पर यह आरोप था कि वे भोले-भाले आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं। इस घटना की जांच करने वाले वाधवा आयोग के अनुसार पॉस्टर स्टेन्स न तो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और न ही उस इलाके, जिसमें वे सक्रिय थे, में ईसाई आबादी के प्रतिशत में कोई वृद्धि हुई थी। धार्मिक स्वतंत्रता एक मानव और सामाजिक अधिकार तो है ही वह एक संवैधानिक अधिकार भी है। ईसाईयों और मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हिंसा इस अधिकार का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है।

जाति है कि जाती नहीं

हर्ष वी. पंत

के मंदिरों से बचने वाले नेता अब मंदिर-मंदिर धूम रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है जैतिवाद से बचने वाले भी अब जॉटिवादी चाशनी का स्वाद चखने को आतुर दिख रहे हैं। यह आचरण इसलिए और भयावह है कि खुद को श्रेष्ठजन कहने वाले भी यदि वैसा ही आचरण प्रदर्शित करेंगे तो छाटी-छोटी पार्टियों का जॉटिवादी लबादा कैसे उतरेगा और फिर वह इन्हें किस मुह से जॉटिवादी कह पाएंगी।

उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो दिखता है उसमें समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों के सहारे अपनी राजनीतिक नाव खेती रही है। बहुजन समाज का मुख्य वोट बैंक जाटव रहे हैं। अपना दल कुर्मियों का ठंका लिये धूम रहा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महज चार-पांच जिलों में रहने वाली बमुश्किल आधा प्रतिशत जारीय हस्सेदारी वाली राजभर जाति के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कीशिश में है। निषाद पार्टी केवट-निषाद-मल्लाह जॉटियों की ठेकेदार बनी धूम रही है। ऐसे ही महान दल, पीस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल आदि पार्टियां एक-एक, दो-दो जॉटियों के भरोसे अपना-अपना झंडा लिए इधर-उधर टहल रही हैं। इन्हीं के बीच हैदरबाद से आए असदद्दीन ओवैसी मस्लिम समाज

को गोलबंद करते हुए समाजवादी पार्टी का खेल खराब करने की कोशिश में हैं। कुल मिलाकर उत्तरप्रदेश जातियों की लड़ाई की रणभूमि बना हुआ है। जातियों के बटवारे के इस खेल में दो बड़े राजनीतिक खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी कूद पड़े हैं। वह भले ही पच्छान्त तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर खेल वही है। क्या यह कम अधेरगर्दी नहीं है कि यहां राजनीति करने वाली तीन पार्टियों ने तो एक ही जाति के नेताओं को अपना-अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है सारी पार्टियां पिछड़ा-पिछड़ा खेल रही हैं। इस राजनीतिक खेल में समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर चला गया है। उसकी गरीबी और हालात पर सबने आंखें बंद कर रखी हैं। सर्वांग समाज पर कोई अत्याचार अनाचार होता है तो उस पर चुप्पी साधने की प्रवृत्ति भी इन दिनों राजनीति का हिस्सा हो चली है। इससे राजनीति शास्त्र के किन सिद्धान्तों के जरिये सामाजिक ताना-बाना मजबूत हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि सम्मेलनों की आड़ में भाजपा बीते एक पखवाड़े से राजथानी लखनऊ में जातियों की जो जुटान कर रही है उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का यह बयान कर प्रारंभिक नहीं है कि 'भाजपा तो जाति पर जाति निकाल रही है।' अखिलेश यादव की परेशानी की वजह भी यही है कि पिछड़ों का नाम लेकर उनवे पिता मुलायम सिंह यादव और बाद में वह जातियों की उंडेकारी कर रहा

